

प्रेषक,

अनरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास विभाग,
उत्तरांचल, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग

देहरादून : दिनांक : 30 नवम्बर, 2006

विषय: नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी हेतु अवस्थापना विकास निधि से वित्तीय वर्ष 2005-06 में सी.सी.सड़कों हेतु स्वीकृत कार्यों को टाइल्स सड़कों में परिवर्तित करने के फलस्वरूप संशोधित आगणन पर वित्तीय वर्ष 2006-07 में प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 454/V-श.वि.-06-32(सा.)/06, दिनांक 6.3.2006 एवं शासनादेश संख्या 801/V-श.वि.-06-166(सा.)टी.सी./03 दिनांक 29.3.2006 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश द्वारा स्वीकृत सी.सी. सड़कों को टाइल सड़कों में परिवर्तित किए जाने हेतु नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी द्वारा प्रस्तुत संशोधित आगणन रु. 75.50 लाख के तकनीकी परीक्षणोपरान्त, संलग्न सूची में अंकित विवरणानुसार रु. 67.35 लाख की रास्तुति की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 6.3.2006 द्वारा स्वीकृत रु. 103.45 लाख के सापेक्ष शासनादेश दिनांक 29.3.2006 द्वारा मात्र रु. 95.04 लाख की धनराशि आहरित करने के निर्देश जारी किए गये थे। इस प्रकार पूर्व स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष भी रु. 8.41 लाख अवनुक्त होने हेतु शेष है।

2- अतएव उपरोक्त संशोधित आगणन की संस्तुत धनराशि रु. 67.35 लाख व पूर्व में शासनादेश दिनांक 6.3.2006 द्वारा सी.सी. सड़कों हेतु स्वीकृत धनराशि रु. 47.79 लाख के बीच अन्तर की धनराशि रु. 19.56 लाख तथा उपरोक्त शासनादेश दिनांक 06-3-06 की अवशेष रु. 8.41 लाख, इस प्रकार कुल रु. 27.97 लाख (रु. सत्ताईस लाख सत्तानबे हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. उक्त धनराशि आपके द्वारा आहरित कर संबंधित कार्यवाही संस्थाओं को बैंक ड्राफ्ट अथवा चेक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. अवस्थापना विकास मद से स्वीकृत की जा रही धनराशि को स्थानीय निकायों के द्वारा अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी का संयुक्त रूप से एक पृथक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोल कर जमा किया जायेगा। किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य मदों में न किया जाय। इसके लिए संबंधित अधिशासी अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं योजनाओं एवं मदों के लिए किया जायेगा, जिन योजनाओं एवं मदों के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन किसी अन्य योजना/मद में नहीं किया जायेगा।
4. टाइल सड़कों के निर्माण हेतु शासनादेश सं०-3173/V-श.वि०-2006, दिनांक-30 अगस्त, 2006 जो वित्त विभाग की सहमति से जारी किया गया है, का अनुपालन बाध्यकारी होगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय अथवा निर्माण करने से पूर्व सभी योजनाओं/कार्यों पर संबंधित मानचित्र एवं विस्तृत आगणन गठित कर तकनीकी दृष्टिकोण से समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुए एवं विशिष्टियों का अनुपालन करते हुए प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा। बिना प्राविधिक स्वीकृति के किसी भी दशा में कार्य को प्रारम्भ न किया जाय।

(मायावती दफ्तरियाल)

अनु.सचिव
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

6. कार्य पर उतना ही ध्यान दिया जाए, जितना कि स्वीकृत नाम है। स्वीकृत नाम से अधिक ध्यान कदापि न दिया जाए।
7. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।
8. संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा निर्माण कार्य निर्धारित अवधि के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना आवश्यक होगा और किसी भी दशा में पुनरीक्षित आगणनों पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी के अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
9. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तापुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर परचेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये। एकमुश्त प्राविधान के विस्तृत आगणन गठित कर लिये जाये और इन पर यदि किसी तकनीकी अधिकारी के कार्य कराने से पूर्व का अनुमोदन प्राप्त करना नियमानुसार आवश्यक हो तो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उक्त अनुमोदन अवश्य प्राप्त कर लिया जाये।
10. निर्माण एजेंसी के चयन में शासनादेश संख्या 452/XXVII(1)/2005 दिनांक 05 अप्रैल 2005 में निर्गत निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।
11. यदि उक्त कार्य अन्य विभागीय/नगर निकाय के बजट से स्वीकृत हो चुके हैं या कराये जा चुके हैं, तब संबंधित योजना/कार्य के लिए इस शासनादेश द्वारा अवमुक्त की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण न करके उसकी सूचना शासन को देकर आवश्यक धनराशि शासन को तत्काल समर्पित कर दी जायेगी।
12. कार्य करने के बाद कार्य स्थान पर योजना के पूर्ण विवरण के साथ अर्थात् योजना की लागत, लम्बाई, कार्यदायी संस्था, ठेकेदार का नाम, प्रारम्भ करने का समय, पूर्ण करने का समय तथा वित्त पोषण के श्रोत के विवरण के साथ एक साइनबोर्ड उक्त योजना की लागत से ही लगा दिया जायेगा।
13. जी.पी.डब्ल्यू. फॉर्म-9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य पूर्ण न करने पर निर्माण इकाई से आगणन की कुल लागत का 10 प्रतिशत की दर से दण्ड वसूल किया जायेगा।
14. सभी निर्माण कार्य समय-समय पर गुणवत्ता एवं मानकों के संबंध में निर्गत शासनादेशों के अनुरूप कराये जायेंगे तथा यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों को पूर्ण नहीं करते हैं तो संबंधित संस्था को अप्रैतर्त धनराशि उक्त मानकों को पूर्ण करने पर निर्गत की जायेगी। निर्माण एजेंसी को एकमुश्त पूर्ण धनराशि अवमुक्त न करके दो अथवा तीन किश्तों में धनराशि अवमुक्त की जायेगी और अंतिम किश्त तब ही निर्गत की जाये, जब कार्य की गुणवत्ता ठीक हो, शासनादेश के मानकों के अनुरूप हो।
15. आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण संबंधित विभाग के अधिशासी अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों तथा जो दरें शिड्यूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा। तदोपरान्त ही आगणन की स्वीकृति मान्य होगी।
16. उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि की प्रतिपूर्ति का प्रस्ताव अविलम्ब शासन को प्रेषित किया जायेगा।
17. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
18. विस्तृत आगणन में ली जाने वाली दरों का अनुमोदन निकटतम लोक निर्माण के अधिशासी अभियन्ता से आवश्यक होगा एवं कार्य कराने से पूर्व समस्त कार्यों का स्थल निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लिया जाए एवं स्थल पर आवश्यकतानुसार ही कार्य किये जायेंगे।
19. निर्माण कार्य पर प्रयोग किये जाने वाली सामग्री का नमूना परीक्षण अवश्य करा लिया जाये तथा उपयुक्त पायी गयी सामग्री का ही प्रयोग निर्माण कार्य में किया जाये।

(मायावती दफ्तरियाल)

अनुमोदित
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

20. कार्य 31-3-07 तक पूर्ण कर इसी वित्तीय वर्ष में उक्त कार्यों की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को तथा उपयोगिता प्रमाणपत्र भी शासन को उपलब्ध करा दिया जाये।
21. कार्यों की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूप से उत्तरदायी होंगे।
22. मुख्य सचिव महोदय, उत्तरांचल शासन के शासनोद्देश संख्या 2047/XIV-219/2006 दिनांक 30मई, 2006 के द्वारा निर्गत आदेशों के क्रम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय का कड़ाई से पालन किया जाए।

3- उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या 13 के आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्षक "2217-शहरी विकास-03- छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास-आयोजनागत-191-स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता-03-नगरों का समेकित विकास-05- नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास" के मानक मद '20 सहायक अनुदान/अंशदान/ राज सहायता' के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या : 554/XXVII(2)/2006 दिनांक 09 नवम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या 2280(1)/V/2006 तददिनांक 30/11/06

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तरांचल, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा. नगर विकास मंत्री जी।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
4. जिलाधिकारी, उत्तरकाशी।
5. परिषद कोषाधिकारी, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, बजट अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि नगर विकास के जी.ओ. में इसे शामिल करने का कष्ट करे।
8. अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, उत्तरकाशी।
9. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

(मायावती दकरियाल)
अनुपस्थित
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन

आज्ञा से
(एन. के. जोशी)
अपर सचिव।

क्र०सं०	मद का नाम	टाईल सड़क के रूप में संशोधित आगणन लागत (लाख रु० में)	टी०ए०सी० से अनुमोदित (लाख रु० में)
01	वार्ड न०-1 में परिषद भवन संस्कृति महाविद्यालय (उजेली) से बेसिक स्कूल खाण्ड रोड तक सी०सी० टाईल सड़क/नाली/दिवार/रैलिंग कार्य	27.33	25.00
02	वार्ड न०-2 में भटवाडी मोटर मार्ग से गोफियारा में जल निगम कालोनी की तरफ सी०सी० टाईल के साथ हल्का वाहन का निर्माण।	11.14	9.00
03	वार्ड न०-8 में श्री कण्डारी के मकान के पास से श्रुतिया खेत तक सी०सी० टाईल सड़क/नाली निर्माण कार्य	6.53	5.70
04	वार्ड न०-8 ज्ञानसू में भट्टा होटल के पास से पुलिस लाइन तक सी०सी० टाईल सड़क/नाली निर्माण कार्य	7.85	6.70
05	वार्ड न०-8 व 9 ज्ञानसू में काकुडीघार से कन्या हाईस्कूल मैणागाड तक सी०सी० टाईल सड़क एवं तल्लबन्दी कार्य	22.65	20.95
	कुल योग-	75.50	67.35

नोट :- पूर्व शासनादेश के अवशेष रु० 8.41 लाख एवं टाईल सड़कों के अन्तर (रु० 67.35 - रु० 47.99 = रु० 19.65) सहित रु० 27.97 लाख की धनराशि अब स्वीकृत की जा रही है। (रुपये सत्ताईस लाख सत्तानबे हजार मात्र)

राम
(मायावती टकरियाल)
अनुमोदित
शहरी विकास विभाग
उत्तरांचल शासन